

3



विजन डाबू नेट
एक रोडमैप की
तरह है

5



वैक्या प्रभावशाली
नेता और प्रखर
वक्ता रहे हैं

6



जशरी है परमाणु
जवाबदेही बाधाओं
से मुक्ति

RNI-MPBIL/2011/39805

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

जगत प्रवाह

वर्ष : 16 अंक : 04

प्रति सोमवार, 2 जून 2025

मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

राष्ट्र निर्माण में नारी शक्ति के अमूल्य योगदान का प्रतीक देवी अहिल्याबाई : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

मोदी जी के नेतृत्व में कीर्तिमान रच रहा भारत : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

(विद्युत्तल माध्यम से)



कवर स्टोरी
-विजया पाठक
एडिटर

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 31 मई को लोकमाता देवी अहिल्याबाई डोलकर के 300वीं जयंती वर्ष के अवसर पर भोजपुर आये। जम्मूरी मैदान पर महिला सराधिकारण महासम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा

का प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार लोकमाता अहिल्याबाई के इन्हीं मूल्यों पर चलते हुए कार्य कर रही है, "नर्तक देवी भवः" वर्तमान में गवर्नेस का मंत्र है। लोकमाता देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती, सभी देशवासियों के लिए प्रेरणा और राष्ट्र निर्माण के लिए हो रहे भागीरथी प्रयासों में अपना योगदान देने का अवसर है। देवी अहिल्याबाई का मानना था कि "जनता की सेवा और उनके जीवन में सुधार लाना ही शासन का उद्देश्य है", उनकी इस सोच को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार यूनेस

लेड डेवलपमेंट के विज्ञान को विकास की धुरी बना रही है, सरकार को हर बड़ी योजना के केंद्र में मातार-बहने-बेटियां हैं। देश में गरीबों के लिए चार करोड़ घर बनाए जा चुके हैं और इनमें से अधिकतर घर माता-बहनों के नाम पर हैं, वे पहली बार घर की मालकिन बनी हैं। सरकार हर घर तक नल से जल पहुंचा रही है, माता-बहनों को अस्सीविधा न हो और बेटियां पढ़ाई सिखाई में ध्यान दे सकें, इस उद्देश्य से बिजली, उच्चवर्ग गैस भी उपलब्ध कराई गई हैं। यह सुविधाएं माता बहनों के सम्मान का प्रयास हैं। (विस्तृत पेज 2 पर)

कि लोकमाता देवी अहिल्याबाई राष्ट्र निर्माण में नारी शक्ति के अमूल्य योगदान

छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री साय के कुशल नेतृत्व में तैयार हुई नक्सलवादी आत्मसमर्पण, पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति

-विजया पाठक

छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण, पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति-2025 को मंजूरी प्रदान की, जिसके तहत सरेंडर करने वाले माओवादियों को वित्तीय सहायता, शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने राज्य में नक्सल समस्या के समाधान के लिए ठोस पहल करते हुए छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति-2023 के स्थान पर छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण/पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति-2025 को मंजूरी प्रदान की है।

'नक्सलवाद खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम'

इस नीति के तहत सरेंडर करने वाले माओवादियों को आर्थिक सहायता, पुनर्वास, शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। अधिकारियों ने बताया कि इस नीति के तहत सरेंडर करने वाले माओवादियों को कई तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। इनमें आर्थिक मदद, पुनर्वास की व्यवस्था, शिक्षा और रोजगार के अवसर शामिल हैं। साथ ही, उनकी सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। सरकार का मानना है कि यह कदम नक्सलवाद को कम करने में कारगर साबित होगा। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार नक्सल समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है और यह नीति उस दिशा में एक बड़ा कदम है।

अधिकारियों को दी जाएगी ट्रेनिंग

अधिकारियों ने बताया कि बैठक में यह भी तय किया गया कि सरेंडर करने वाले नक्सलीयों को सम्मान में दोबारा बसाने के लिए विशेष योजनाएं बनाई जाएंगी। उन्हें ट्रेनिंग देकर आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, जिससे वे हिंसा का रास्ता छोड़कर सम्मानजनक जीवन जी सकें। इसके अलावा, नक्सल हिंसा से प्रभावित लोगों के लिए भी राहत और पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। (रोष पेज 3 पर)



राष्ट्र निर्माण में नारी शक्ति के अमूल्य योगदान का प्रतीक देवी अहिल्याबाई : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

महासम्मेलन की प्रमुख बातें

• पहली बार महिलाओं को सौंपे गए सभी दफिवा। • लगभग दो लाख महिलाओं की रहीं सहभागिता। • महिला सशक्तिकरण योजनाओं की प्रस्तुति। • प्रधानमंत्री मोदी ने किया इंदौर मेट्रो का शुभारंभ और दतिया व सतना एयरपोर्ट का लोकार्पण। • प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदेश के 1271 अटल ग्राम सेवा सदन के लिए 483 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की। • नरेंद्र मोदी ने लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। • प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पगड़ी पहना कर तथा बैतुल जिले के भरेवा शिला से निर्मित पुष्पक डिमल गेट कर उनका स्वागत किया। • नरेंद्र मोदी का महिला सशक्तिकरण और स्वावलंबन की प्रतीक पट्टे की चार महिलाओं ने भी स्वागत किया। • प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ की जनजातीय कलाकार डॉ. जयमती कश्यप को देवी अहिल्या बाई राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया। • प्रधानमंत्री श्री मोदी ने लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर को समर्पित डाक टिकट और 300 रुपये का सिक्का जारी किया।



(पेज 1 का विस्तृत)

हर क्षेत्र में सराका हो रही महिलाएं: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज बेटीयां डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट बन रही हैं। गांव-गांव में बैंक सविधाएं बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत कर रही हैं। एक समय था, जब महिलाओं को नई तकनीक से दूर रखा जाता था लेकिन आज गांव की बहनें ड्रोन टीवी बनकर खेती में मदद कर रही हैं। गांव में उनकी अलग पहचान बन रही है। पहले महिलाएं अपनी बीमारियां छिपाती थी, क्योंकि परिवार पर इलाज का बोझ न पड़े लेकिन अब महिलाएं आयुष्मान योजना में 05 लाख तक का निःशुल्क इलाज करा सकती हैं। गल 11 साल में हमारी केन्द्र और राज्य की सरकारों ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किया है। हमारी सरकार ने 30 करोड़ जनधन खाते खुलवाए हैं, जिनमें उन्हें पैसे भेजे जा रहे हैं। बहनें आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं। मुद्रा षेजना का लाभ लेने वाली ज्यादातर महिला उद्यमी हैं। देशभर में 10 करोड़ बहनें स्व-सहायता समूह से जुड़ी हैं और कमाई कर रही हैं। सरकार ने 03 करोड़ बहनों को लक्ष्मि टीटी बनाने का संकल्प लिया है। नयी ड्रोन योजना के अंतर्गत अब तक 1.5 करोड़ बहनें लक्ष्मि बन चुकी हैं। देश में सॉलर और मध्य पड़ने वाली बेटीयों को संख्या लगातार बढ़ रही है। चंद्रयान 3 मिशन में 100 से अधिक महिला वैज्ञानिक शामिल

थीं। देश में स्टार्टअप की संख्या बढ़ रही है, इनमें 45 प्रतिशत नेतृत्व महिलाओं के पास है। हमारी सरकार में पहली बार पूर्णकालिक महिला राश और वित्त मंत्री बनीं। इस बार 75 सांसद महिलाएं हैं, पंचायतों में भी महिला प्रतिनिधियों की भारीदारी बढ़ रही है। सरकार के नारी शक्ति बंदन अभिनय के पीछे भी यही भावना है। अब संसद और विधानसभाओं में भी महिला आरक्षण दे दिया गया है। भारत सरकार बहनों को हर क्षेत्र में सशक्त कर रही है। उनके संकल्पों से सीख मिलती है कि परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो इच्छाशक्ति से उन्हें पूर्ण किया जा सकता है। आज से 250-300 साल पहले जब देश मुसली की बेटीयों में जकाड़ा था, तब उन्होंने इन कर्तव्यों को पूर्ण किया। वे हमेशा शिवलिंग साथ लेकर चलती थीं। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में राज्य का कार्यभार संभाला और राज्य को समृद्धि दी। देवी अहिल्याबाई भारत की विरासत की संरक्षक थीं। जब देशभर में हमारे मंदिरों, तीर्थ स्थलों पर हमले हो रहे थे तो उन्होंने इन्हें संरक्षित करने का कार्य किया। उन्होंने काली विरचनाथ समेत अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वह उनका सौभाग्य है कि काली ने उन्हें भी सेवा का अवसर दिया है। काली ने देवी अहिल्याबाई की मूर्ति भी देखने को मिलती है।

केन्द्र के साथ कदम से कदम मिलाकर विकास पथ पर आगे बढ़ रहे राज्य सरकार: मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि भारत ने जगान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया में शिक्षा पर पहुंचेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने आतंकी सरकार और आतंकवादियों को धूल चटाई। पुरा देश आपका अभिनेता बन रहा है। जिन आतंकियों ने बहनों का सिंदूर उड़ा देने का काम किया, उन्हें सबक सिखाया है। मध्यप्रदेश सरकार गरीब, किसान, युवा और नारी सहित हर वर्ग के कल्याण के लिए केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को बैतुल के भरेवा शिला निर्मित पुष्पक विमान की कृति भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी ने देवी अहिल्याबाई होल्कर को समर्पित डाक टिकट और सिक्का जारी किया।

मोदी ने किया लोकमाता देवी अहिल्याबाई पर केंद्रित प्रदर्शनी का अवलोकन

प्रधानमंत्री ने प्रदर्शनी में लोकमाता अहिल्या बाई द्वारा सूर्यसन, महिला स्वावलंबन, धार्मिक स्थलों के उन्नयन के लिए संचालित गतिविधियों को प्रदर्शित किया गया। इसके साथ ही देवी अहिल्या पर केंद्रित पुस्तकें और शोध पत्र भी प्रदर्शित किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने हथकरघा-हस्तशिल्प को समर्पित महिलाओं और ड्रोन टीवी से संवाद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिए जारी गतिविधियों, ग्रामीण अवसर योजना, ग्रामीण पर्यटन, कृषि आदि क्षेत्र में महिलाओं द्वारा की जा रही पहल और ग्रामीण व नगरीय निवासियों में महिला प्रतिनिधित्व के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदर्शनी में प्रदेश में अधोसंरचना विकास के अंतर्गत संचालित गतिविधियों, विभिन्न धार्मिक लोक के विकास सहित राज्य के अन्य विकासोन्मुखी नवाचारों का भी अवलोकन किया।

दतिया और सतना एयरपोर्ट का लोकार्पण तथा इंदौर मेट्रो का भी शुभारंभ

प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदेश में 1271 नए अटल ग्राम सेवा सदन (पंचायत भवन) निर्माण के लिए प्रथम किस्त के अंतर्गत 483 करोड़ रुपये का वर्षुअल अंतरण भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंदौर मेट्रो की शुरुआत और दतिया व सतना के हवाई सेवा से जुड़ने से मध्यप्रदेश में सुविधाएं बढ़ेंगी, विकास को गति मिलेगी और रोजगार के नए अवसरों का इससे सृजन भी होगा। मध्यप्रदेश में अनेक विकास के कार्य हो रहे हैं। भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को अब मेट्रो की पहचान मिली है। केंद्र सरकार ने मालवा क्षेत्र में परिवहन सुविधाओं के विस्तार के लिए रेल लाइनों के विकास को मंजूरी दी है। दतिया व सतना के हवाई सेवा से जुड़ने से अब मां पीतांबर और मां शारदा देवी के दर्शन और सुलभ हो जाएंगे। बुंदेलखंड और बघेलखंड की कनेक्टिविटी बढ़ेगी।

प्रधानमंत्री मोदी ने किया प्रदर्शनी का अवलोकन, सशक्त महिलाओं से किया संवाद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जयंती के अवसर पर महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में लोकमाता देवी अहिल्याबाई पर केंद्रित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। राज्यापाल मंगुभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी इस अवसर पर उपस्थित थे। लोकमाता अहिल्या बाई द्वारा सूर्यसन, महिला स्वावलंबन, धार्मिक स्थलों के उन्नयन के लिए संचालित गतिविधियों को प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। इसके साथ ही देवी अहिल्या बाई पर केंद्रित पुस्तकें और शोध पत्र भी यहां प्रदर्शित हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हथकरघा-हस्तशिल्प को समर्पित महिलाओं और ड्रोन टीवी से संवाद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिए जारी गतिविधियों, ग्रामीण अवसर योजना, ग्रामीण पर्यटन, कृषि आदि क्षेत्र में महिलाओं द्वारा की जा रही पहल और ग्रामीण व नगरीय निवासियों में महिला प्रतिनिधित्व के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदर्शनी में प्रदेश में अधोसंरचना विकास के अंतर्गत संचालित गतिविधियों, धार्मिक लोकों के विकास, सहित राज्य की अन्य विकासोन्मुखी नवाचारों का भी अवलोकन किया।

मुख्यमंत्री साय ने रायपुर और धमतरी जिले में योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की विजन डाक्यूमेंट एक रोडमैप की तरह है: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

-शशि पांडे

जगत प्रवाह, रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर और धमतरी जिले में योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि 'विश्वसित छत्तीसगढ़' के लिए तैयार किया गया विजन डाक्यूमेंट एक रोडमैप की तरह है, जिसमें लक्ष्य और दिशा-निर्देश स्पष्ट हैं। अधिकारी विश्वसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को साकार करने के लिए पूरी तन्मयता और जिम्मेदारी के साथ इसे परिणाम तक ले जाएं।

मुख्यमंत्री ने सुरासन तिहार के समापन पर कहा कि लोगों की समस्याओं के समाधान का यह सिलसिला धमना नहीं चाहिए। जन-जन से संवाद और उनकी समस्याओं का समाधान निरंतर जारी रहना चाहिए। अधिकारी कड़ी मेहनत और नवाचारी तरीकों से लोगों की समस्याओं का समाधान करें। आम जनता को देरी से न्याय मिलना, न्याय नहीं मिलने के बराबर है। उन्होंने कहा कि राजस्व जुटे सुधार जैसे कार्यों में अधिकारियों-कर्मचारियों से ही गलती होती है, लेकिन इसका नुकसान आम लोगों को होता है और उन्हें ही परेशान होना पड़ता है।

मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग में डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने और समय प्रबंधन पर ध्यान देने की बात कही। उन्होंने कहा कि सक्रिय तहसीलदारों वाले क्षेत्रों में राजस्व प्रकरण कम लंबित रहते हैं। साथ ही, अधिकारियों को जनता के साथ अच्छा व्यवहार करने और उनके कार्यों को न्यूनतम समय में गुणवत्तापूर्वक पूरा करने का निर्देश दिया।

पलैंगशिप योजनाओं पर दें ध्यान

मुख्यमंत्री ने बैंड और राज्य सरकार की पलैंगशिप योजनाओं, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम आवास, और जल जीवन मिशन को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि फसल बीमा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा सर्वोत्कृष्ट राज्य चुना गया है। साथ ही, नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री

नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार धमतरी और रायपुर में पर्यटन स्थल विकसित करने की संभावनाओं को तलाशने को कहा।

मुख्यमंत्री ने जिले में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने दत्तेवाड़ा का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां डीईओ के बेहतर प्रदर्शन के कारण दसवीं और बारहवीं के परिणाम शतान्वार रहे, जिसकी प्रधानमंत्री ने 'मन की बात' में प्रशंसा की। स्वास्थ्य विभाग में सतत मॉनिटरिंग और संस्थापनों

की उपलब्धता सुनिश्चित करने, साथ ही कुषि प्रधान धमतरी और रायपुर जिले में खरीफ फसल की तैयारी और किसानों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने पर बल दिया।

अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे योजनाओं का लाभ

मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से विभागीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों को खड़ा करने को कहा, ताकि राज्य स्तर पर सहजता प्रदान की जा सके। उन्होंने यह भी बताया कि अधिकारियों के

कार्यों की निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है और प्रत्येक जिले का रिपोर्ट कार्ड उनके पास है। उन्होंने कहा कि सुरासन तिहार के दौरान अधिकारियों ने बड़ी संख्या में आए आवेदनों का समयबद्ध समाधान किया, जिसके लिए वे बहाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों को अच्छा काम करने पर पुरस्कार और काम नहीं करे तो उनकी खैर नहीं होगी। इस मौके पर वन मंत्री केदार कश्यप, राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा, सांस्कृतिक विभाग के कुमारी चौधरी, विधायक अजय चंद्राकर, विधायक ओंकार साहू, महापौर रामू रोहता, जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सावंत, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष नेहरू निषाद, अपर मुख्य सचिव श्रीमती रेणु पिल्ले, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव बसव राजू एस, साहित्य रायपुर और धमतरी जिले के अधिकारी उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री साय के कुशल नेतृत्व में तैयार हुई नक्सलवादी आत्मसमर्पण, पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति

(पेज 1 से जारी)

'नई उम्मीद लेकर आई ये नीति'

उन्होंने बताया कि यह नीति छत्तीसगढ़ में लंबे समय से चली आ रही नक्सल समस्या के समाधान के लिए एक नयी उम्मीद लेकर आई है। सरकार का दावा है कि इससे न केवल नक्सलियों को मुख्यधारा में जोड़ने में मदद मिलेगी, बल्कि राज्य में शांति और विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।

साय सरकार को मिली बड़ी सफलता

छत्तीसगढ़ में साय सरकार को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। राज्य से नक्सली हिंसा खत्म करने की कोशिशों में जुटे प्रशासन के लिए 27 मई का दिन खास रहा। 18 नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ हथियार जालते हुए सरेंडर कर दिया। इनमें एक महिला भी शामिल है। इनमें कुछ नक्सली मूवमेंट के बड़े नाम भी हैं। इस सफलता के पीछे स्थानीय प्रशासन, पुलिस और सुरक्षा बलों के अथक प्रयास तो हैं ही। साथ में केंद्र सरकार की एक खास योजना भी है, जिसने नक्सलियों को हथियार छोड़कर घर वापस लौटने को प्रेरित किया। जिन 18 नक्सलियों ने सरेंडर

किया है, उनमें से 10 के सिर पर तो कुल 39 लाख रुपये का इनाम था। इन सभी ने कल चोखनार को सुकमा जिले में आत्मसमर्पण कर दिया। इन नक्सलियों में कुछ बड़े नाम भी हैं। मसलन PLGA बटालियन नंबर एक के मेजर मइकम आयात और भास्कर उर्फ भोगम लक्ष्मा। इन दोनों पर 8-8 लाख का इनाम था। मइकम कमल और लक्ष्मण उर्फ मादवी चानू पर 5-5 लाख का इनाम था। जबकि 6 नक्सली ऐसे भी हैं, जिन पर 2-2 लाख रुपये का इनाम था।

सरकार की इस योजना से हुए प्रभावित

इन सभी नक्सलियों के बीच एक बात बँधन रही है। सभी का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार की एक योजना से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़ने का फैसला कर लिया। इस योजना का नाम है, 'निपट नेल्लानर योजना'। हिंदी में इसका मतलब है 'हमारा स्वच्छ गांव'। इस योजना के अलावा केंद्र सरकार की ओर से लागू सरेंडर पॉलिसी नक्सलियों को वापस से मुख्यधारा से जोड़ने में सफल हो रही है। निपट नेल्लानर योजना के तहत बसने में काफी सारे विकास कार्य चल रहे हैं।

जिला स्थापना शाखा कार्यालय का निरीक्षण



-अमित राय

जगत प्रवाह, बक्सर। जिला पदाधिकारी बक्सर, अशुल अग्रवाल द्वारा जिला स्थापना शाखा कार्यालय का निरीक्षण किया गया। राजस्व कर्मचारियों, लिपिकों एवं अन्य कर्मियों के विरूद्ध विभिन्न स्तरों पर लंबित विभागीय कार्रवाई के संबंध में स्थापना उप समाहर्ता बक्सर को निर्देश दिया गया कि 15 जून 2025 तक सभी पदाधिकारियों से प्रतिवेदन प्राप्त करते हुए करवाई/दंड अभिरोधन हेतु प्रस्ताव उपस्थापित करेंगे। मानव संसाधन प्रणाली के अंतर्गत अथकश प्रबंधन, सेवा सात्पापन, कैडर प्रबंधन, आरटीआई प्रोपण, लोन रिकवरी इत्यादि कार्यों में प्रगति अस्तोषजनक पाया गया। स्थापना उप समाहर्ता बक्सर को निर्देश दिया गया कि जिन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त नहीं है, उनका स्तोषजनक प्रतिवेदन प्राप्त होने तक माह मई 2025 का वेतन भुगतान स्थगित करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही एक सप्ताह के अंदर प्रगति प्राप्त करने का निर्देश दिया गया। कार्यस्थल

एवं कार्यालय परिसर की स्वच्छता की समीक्षा की गई एवं स्थिति अस्तोषजनक पायी गयी। स्थापना उप समाहर्ता बक्सर सह मोडल पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त निदेश के आलोक में स्थापना शाखा के साथ साथ समारणालय के सभी कार्यों एवं परिसर में स्वच्छता हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे। निरीक्षण के क्रम में स्थापना लिपिक जगनारायण राय द्वारा सही प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराने के कारण उनसे कारण पूछा करने का निर्देश दिया गया। निरीक्षण के क्रम में प्राप्त एवं विगष्टन पत्रों की संख्या में काफी अंतर पाया गया। इसके साथ-साथ उपस्थित पंजी, अवकाश पंजी, माई संचिका एवं अन्य संचिकाओं का निरीक्षण किया गया। स्थापना उप समाहर्ता बक्सर को विभागीय निदेश के आलोक में कर्मियों के स्थानांतरण का प्रस्ताव उपस्थापित करने का निर्देश दिया गया। स्थापना उप समाहर्ता बक्सर को नियमित रूप से कार्यालय का निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया। कार्यस्थल

किसानों ने समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदने हेतु ज्ञापन दिया

-प्रमोद बरसले

जगत प्रवाह, रिटजनगी। भारतीय किसान संघ द्वारा प्रदेश भर में मूंग फसल को समर्थन मूल्य पर खरीदी करने हेतु मुख्यमंत्री के नामे तहसील स्तर पर अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। इसी को लेकर भाकिरस ग्राम ईकाई कपासी के अध्यक्ष विष्णु बाकि के साथ अन्य किसानों द्वारा भी मुख्यमंत्री के नामे



रहटगांव तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। जिसमें लिखा कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रतिवर्ष समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी की जाती रही है, जिसके पंजीयन सहित समस्त प्रक्रियाएं अप्रैल मई माह में प्रारंभ हो जाती हैं परन्तु इस वर्ष मध्यप्रदेश शासन द्वारा मूंग खरीदी के पंजीयन से संबंधित कोई भी क्रियाकलाप प्रारंभ नहीं किया गया है, जिससे किसानों में काफी नाराजगी है। समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी नहीं होने से किसानों को लाखों रुपए का नुकसान होगा। इसलिए समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी के आदेश शीघ्रता से करने की कृपा करें।

सम्पादकीय हिंदी पत्रकारिता वर्तमान चुनौतियां और उनका समाधान

30 मई, 1826 को भारत में हिंदी पत्रकारिता की नींव रखी जाती है। पत्रकारिता के अविच्छिन्नता देवर्षि नारद के जयंती प्रसंग पर हिंदी के पहले समाचार-पत्र 'उदंत मर्तंड' का प्रकाशन होता है। हिंदी पत्रकारिता का सुत्रघट होने पर संग्रहादक पंडित जुगल किशोर समाचार-पत्र के पहले ही पृष्ठ पर अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हुए उदंत मर्तंड का उद्देश्य स्पष्ट करते हैं। आज की तरह लाभ कमाना उस समय की पत्रकारिता का उद्देश्य नहीं था। भारत की स्वतंत्रता से पूर्व प्रकाशित ज्यादातर समाचार-पत्र आजादी के आंदोलन के माध्यम बने। अंग्रेज सरकार के विरुद्ध मुद्दे रहे। यही रुख उदंत मर्तंड ने अपनाया। अत्यंत कठिनाईयों के बाद भी पंडित जुगलकिशोर उदंत मर्तंड का प्रकाशन करते रहे। किंतु, यह संघर्ष लंबा नहीं चला। हिंदी पत्रकारिता के इस बीज को आयु 79 अंक और लगभग डेढ़ वर्ष रही। इस बीज की जीवितता से प्रेरणा लेकर बाद में हिंदी के अन्य समाचार-पत्र प्रारंभ हुए। आज भारत में हिंदी के समाचार-पत्र सबसे अधिक पड़े जा रहे हैं। प्रसार संख्या की दृष्टि से शीर्ष पर हिंदी के समाचार-पत्र ही हैं। किंतु, आज हिंदी पत्रकारिता में वह बात नहीं रह गई, जो उदंत मर्तंड में थी। संघर्ष और साहस की कमी काहीं न काहीं दिखाई देती है। दरअसल, उदंत मर्तंड के घोषित उद्देश्य 'हिंदुस्थानियों के हित के हेतु' का अभाव आज की हिंदी पत्रकारिता में दिखाई दे रहा है। हालांकि, यह भाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन बाजार के बोझ तले दब गया है। व्यवसायिक तौर पर मैं मानता हूँ कि जब तक अंश मात्र भी

'देश हित' पत्रकारिता की प्राथमिकता में है, तब तक ही पत्रकारिता जीवित है। आवश्यकता है कि प्राथमिकता में यह भाव पुष्ट हो, उसकी मात्रा बढ़े। समय आ गया है कि एक बार हम अपनी पत्रकारीय यात्रा का सिंहावलोकन करें। अपनी पत्रकारिता की प्राथमिकताओं को टटोलें। समय के थपेड़ों के साथ आई विसंगतियों को दूर करें। समाचार-पत्रों या कहीं पूरी पत्रकारिता को अपना अस्तित्व बचाना है, तो उदंत मर्तंड के उद्देश्य को आज फिर से अपनाता होगा। अन्यथा सूचना के डिजिटल माध्यम बढ़ने से समुची पत्रकारिता पर अप्रत्याशित होने का खतरा मंडरा ही रहा है।

वास्तव में आज की पत्रकारिता के समक्ष अनेक चुनौतियां मुंह बाएं खड़ी हैं। यह चुनौतियां पत्रकारिता के मूल सिद्धांतों से डिगने के कारण उत्पन्न हुई हैं। पूर्वजों ने जो सिद्धांत और मूल्य स्थापित किए थे, उनको साथ लेकर पत्रकारिता मिशन से प्रेरेशन की ओर जाती, तब संभवतः कम समस्याएं आतीं। क्योंकि मूल्यों और सिद्धांतों की उर्वस्थिति में प्रत्येक व्यवसाय में मर्यादा और नैतिकता का खयाल रखा जाता है। किंतु, जैसे ही हम तथ्य सिद्धांतों से हटते हैं, मर्यादा को लांघते हैं, तब स्वाभाविक तौर पर चुनौतियां सामने आने लगती हैं। नैतिकता के प्रश्न भी खड़े होने लगते हैं। यही आज मीडिया के साथ हो रहा है। मीडिया के समक्ष अनेक प्रश्न खड़े हैं। स्वामित्व, भ्रष्टाचार, मीडिया संस्थाओं में काम करने वाले पत्रकारों के शोषण, स्वाभिमान और स्वतंत्रता के प्रश्न।



सियासी गहमागहमी

विजय शाह और देवड़ा को प्रधानमंत्री के सामने लाने पर खींचतान



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भोपाल दौर के लेकर भाजपा ने पिछले कई समय से तैयारियां आरंभ कर दी थी। हर नेता को पार्टी कार्यालय से दायित्व दिया गया और सभी उस दायित्व का निर्वहन करने के लिए जुट गए। इसी क्रम में जब कार्य विभाजन को लेकर बात प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के नाम को लेकर आई तो पार्टी में ही खींचतान शुरू हो गई। शीर्ष स्तर से दोनों नामों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दूर रखने के सख्त निर्देश मिले। यही नहीं पार्टी नेताओं ने यहां तक निर्देशित किया कि अगर देवड़ा और विजय शाह मोदी जी के आसपास भी गए या उन्हें उनके प्रोटोकॉल में शामिल किया गया तो पार्टी शीर्ष नेतृत्व इस पर सख्त एक्शन ले सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर कितने समय तक शाह और देवड़ा को इस वनवास से गुजरना होगा।

कांग्रेस ने जबलपुर से भरी हुंकार



प्रदेश कांग्रेस ने कमलनाथ के मार्गदर्शन और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में जबलपुर से हुंकार भरना शुरू किया। इसी क्रम में 31 मई को पार्टी ने जबलपुर के शहीद स्मारक के पास विशेष कार्य शुरू किया। इसके तहत महाकौशल की पावन धरा पर एक अनोखा अवसरजहाँ देशभक्ति की भावना, शौर्य की गूंज और वीरता की चमक एक साथ महसूस हुई। कांग्रेस नेताओं ने "जय हिंद सभा" में शामिल होकर भारत माता के वीर सपूतों को श्रद्धा-सुमन अर्पित कर आगामी चुनावों के लिए हल्ला बोल शुरू कर दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि पार्टी नेताओं का यह सिलसिला आगे कितने दिन और चलता है और किस निर्णायक मोड़ पर इसका समापन होगा।

हफ्ते का कार्टून



ट्वीट-ट्वीट

"रेलिंग गली, हाथ धालिए"

"इस्लाम है हज, गुलाम गली"

माहत जोड़े यात्रा के दौरान जब मैं शिवाजी से मिले, तो वे शब्द गेरे

दिल में उतर गए।

कॉल्टिक की कांग्रेस सरकार ने एक

ऐतिहासिक कदम उठाया है — एक ऐसा

अध्यक्षता लया है जो शिवाजी से जो

अधिकार, सुरक्षा और सम्मान देता है।

-राहुल गांधी

कांग्रेस नेता @RahulGandhi



पूर्व कैदीय मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्री वसंतराव नाईक जी को जमानदियत की खर्दिक शुल्कप्रदानगायी।



ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपको स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन प्रदान करे।

-कमलनाथ

प्रेम कांग्रेस अध्यक्ष

@OfficeOfKamNath

राजवीरों की बात

वैकैया नायडू प्रभावशाली नेता और प्रखर वक्ता रहे हैं

समता पाठक/जगत प्रवाह



मुम्बईवासी वैकैया नायडू का जन्म 1 जुलाई, 1949 को आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव चावाटपलेम में हुआ था। उनके पिता स्वर्णवर्मा रैया नायडू और माता रामानामा कृष्ण हैं। नेल्सीर केवीआर कॉलेज से स्नातक के पश्चात उन्होंने विशाखापट्टनम के आंध्र विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की डिग्री हासिल की। एक छात्र नेता और राजनीतिक व्यक्ति के तौर पर नायडू बेहद लोकप्रिय छवि वाले व्यक्ति हैं। वह काफी अच्छे वक्ता हैं और किसानों, ग्रामीणों तथा पिछड़े वर्ग के लोगों के मुद्दे उठाने के लिए जाने जाते हैं। कॉलेज के दिनों से ही वैकैया नायडू आम आदमी के कल्याण में काफी दिलचस्पी रखते थे, विशेष तौर पर किसानों और समाज के दबे-कुचले वर्ग के मुद्दों को लेकर वह गहन चिंतन करते हैं। इसके चलते ही वह काफी कम उम्र से सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में शामिल रहे। स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वाले और आपातकाल के दौर का पुरजोर विरोध करने वाला नेतृत्व उनके लिए हमेशा से प्रेरणा का स्रोत रहा है। अपने तीन दशक के सार्वजनिक जीवन में अवतक श्री नायडू ने इन पदों पर रहकर देश की सेवा की है।

दिसंबर, 1999 से सदस्य, वित्त समिति सदस्य, भारत सरकार जनवरी, 2000 ग्रामीण विकास पर स्नातक समिति, भारत सरकार, 30 सितंबर, 2000 से 1 जुलाई, 2002 ग्रामीण विकास मंत्री, भारत सरकार सदस्य, आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति सदस्य, आर्थिक सुधार पर कैबिनेट समिति 1 जुलाई, 2002 से अक्टूबर 05, 2004 अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी अप्रैल, 2005 उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, अगस्त, 2017 से अवतक देश के उपराष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया।

वैकैया नायडू बेहद प्रभावशाली नेता और वक्ता हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार और अत्याचार खिलाफ काफी मुखरता के साथ मुद्दे उठाए जो लोकतंत्र में वाजिब खतरे हैं। आम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की मांग करते हुए वह आपातकाल के काले दौर में कई दिनों तक जेल में रहे। एक सजग पाठक होने के अलावा वह बेहद स्पष्ट लेखक भी हैं। उन्होंने सामाजिक-राजनीतिक और नीति-निर्माण के कई विषयों पर कई अखबारों और पत्रिकाओं के लिए लेखन का कार्य किया। आंध्र प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने पार्टी को ग्रामीणों के स्तर पर स्लोगन अपनाने के लिए प्रेरित किया और राज्य में कई ग्रामीण इलाकों में जमीनी स्तर से पार्टी के नेतृत्व को मजबूत करने का कार्य किया है। राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर श्री नायडू ने देश भ्रमण किया, विशेष तौर पर ग्रामीण और देहाती इलाकों में पार्टी का आधार स्थापित करने का कार्य किया है। बतौर भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष, श्री वैकैया नायडू जी ने पार्टी को राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य किया।

ध्यान, व्यायाम और सकारात्मक विचारों से खुद को करें तैयार



आज की बात

प्रवीण कवकडू स्वतंत्र लेखक

क्या आप जानते हैं कि आपकी सुबह की शुरुआत ही आपके पूरे दिन और अंततः आपके पूरे जीवन की दिशा तय करती है। हम में से ज्यादातर लोग अपनी पूरी क्षमता से नहीं जी पाते, क्योंकि वे अपनी सुबह को यूँ ही गँवा देते हैं या बिना किसी उद्देश्य के इसकी शुरुआत करते हैं। यकीन मानिए, एक उद्देश्यपूर्ण सुबह की दिनचर्या अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को अविश्वसनीय

रूप से बदल सकता है, फिर चाहे वे पहले से जल्दी उठने वाले व्यक्ति न भी हों। अपनी सुबह को ऊर्जा और उद्देश्य दें। ध्यान, व्यायाम और सकारात्मक विचारों से खुद को तैयार करें। किताबें पढ़ें, अपने लक्ष्य लिखें, और खुद को उस बेहतर संस्करण के रूप में देखें जो आप बनना चाहते हैं। ये आदतें आपको सामान्य से उठाकर असाधारण जीवन की ओर ले जाएंगी।

यहाँ आपकी सुबह खास है?— आपकी सुबह की शुरुआत ही आपके पूरे दिन और आपके पूरे जीवन की दिशा तय करती है। यह केवल एक आदत नहीं, बल्कि आपके जीवन को बदलने का एक शक्तिशाली तरीका है। जब आप अपनी सुबह को जानबूझकर और सकारात्मक रूप से शुरू करते हैं, तो आप अपने दिन को नियंत्रित करते हैं, न कि आपका दिन आपको।

करें, उसे जिर्ण।

व्यायाम करें

सुबह थोड़ा व्यायाम करें, भले ही यह केवल 10-15 मिनट का ही क्यों न हो। यह आपके ऊर्जा स्तर को बढ़ाता है और पूरे दिन के लिए एक सकारात्मक मूड स्थापित करता है। एक चुस्त शरीर एक चुस्त दिमाग का आधार है।

किताबें पढ़ें

व्यक्तिगत विकास, व्यवसाय, या किसी भी ऐसे क्षेत्र में किताबें पढ़ें जो आपके लक्ष्यों के अनुरूप हों। हर दिन कुछ पेज पढ़ने से आप लगातार सीखते और विकसित होते रहते हैं। ज्ञान शक्ति है और आपकी सुबह इसका सबसे अच्छा समय है।

आत्म-चिंतन

अपने विचारों, भावनाओं, लक्ष्यों और आधार को लिखें। यह आत्म-चिंतन (जर्नलिंग) का एक तरीका है, जो आपको स्पष्टता देता है, आपके अनुभवों से सीखने में मदद करता है, और आपकी प्रगति को ट्रैक करता है। जब आप लिखते हैं, तो आप खुद को बेहतर समझते हैं।

ये आदतें आपको "औसत दर्जे" से बाहर निकालकर एक असाधारण जीवन की ओर ले जा सकती हैं। याद रखें, आप अपनी सुबह की शुरुआत कैसे करते हैं, यही तय करेगा कि आप अपना जीवन कैसे जीते हैं। तो, इन बिंदुओं को अपनाएं और अपनी सुबह को चमत्कारी बनाएं। याद रखें आप सुबह की शुरुआत कैसे करते हैं। यही तय करेगा कि आप जीवन कैसे जीते हैं।

इन आदतों से बनाएं चमत्कारी सुबह शांति और स्थिरता

अपने दिन की शुरुआत शांति से करें। इसमें ध्यान, प्राणना, गहरी साँस लेना या तिरफ़ शांत बैठना शामिल हो सकता है। यह आपके मन को शांत करता है, तनाव कम करता है और आपको पूरे दिन के लिए स्पष्टता प्रदान करता है। यह आपके भीतर एक शांत केंद्र स्थापित करने में मदद करता है।

सकारात्मक पुष्टि

अपने लक्ष्यों और आप जिस व्यक्ति बनना चाहते हैं, उसके बारे में सकारात्मक घोषणाएं बोलें या पढ़ें। यह आपके अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है और आपकी क्षमताओं में विश्वास जगाता है। अपने आप से कहें कि आप सक्षम हैं, आप सफल हैं, और आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं।

आदर्श कल्पना करें

अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपने आदर्श जीवन जीने की कल्पना करें। अपने मन में स्पष्ट छवियाँ बनाएं कि आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं और आप वहाँ कैसे पहुँचेंगे। यह आपको प्रेरित रखता है और आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक रोडमैप बनाता है। अपनी सफलता को महसूस



जरूरी है परमाणु जवाबदेही बाधाओं से मुक्ति



प्रमोद भार्गव
वरिष्ठ पत्रकार

पहलामा हमले के बदले में चलाए गए आपरेशन सिंदूर के बाद केंद्र सरकार परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले कानूनों में संशोधन पर विचार कर रही है। अंदाजा है कि आगामी मानसून सत्र में परमाणु कति के लिए अस्तित्व में आए गए नागरिक दायित्व अधिनियम (सीएलएनडीए) 2010 में दो महत्वपूर्ण संशोधन सरकार कर सकती है। इन दो संशोधनों को बड़े सुधारों के रूप में देखा जा रहा है। इस संशोधन के तहत परमाणु संयंत्रों को उपकरण सफाई करने वाली कंपनियों की जिम्मेदारी सीमित की जा सकती है। मसलन यदि कोई दुर्घटना होती है तो उनका जिम्मेदारी अनुबंध की मूल राशि और एक निर्धारित समय तक ही सीमित रहेगी। इस परिप्रेक्ष्य में बाह्य उदाहरण विदेशी कंपनी जैसे जीई-हिताची वैरिंटग हाउस को इस कानून के कारण निवेश में हिचक होती रही है। दूसरा संशोधन परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 में प्रस्तावित है। यह कानून फिलहाल केवल सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों को ही परमाणु संयंत्र चलाने की अनुमति देता है। इसे संशोधित किया जाता है तो निजी कंपनियों को भी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के संचालन की अनुमति मिल सकती है। इस परिवर्तन से विदेशी कंपनियों के लिए भविष्य के परमाणु प्रोजेक्ट में आर्थिक हिस्सेदारी का द्वार खुल जाएगा। साफ है, ये उपाय किए जाते हैं तो परमाणु उत्पादन बढ़ने की संभावनाएं तो बढ़ जाएंगी, लेकिन स्वच्छ ऊर्जा और परमाणु दुर्घटना होने पर कंपनियों को नागरिक जवाबदेही से मुक्ति मिल जाएगी। याद रहे मनमोहन सिंह सरकार के प्रधानमंत्री रहते हुए भारत-अमेरिका के बीच हुए परमाणु समझौते के बाद जो राजनैतिक तुलान उठा था, उसके चलते संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन-1 सरकार गिरे-गिरे बची थी।

दरअसल सरकार परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को बाधा मुक्त इसलिए करना चाहती है जिससे 2047 तक सौ मेगावाट परमाणु ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य

हासिल कर लिया जाए। इसी लक्ष्य पूर्ति के लिए सरकार परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी भागीदारी बढ़ाना चाहती है। इसीलिए 2024-25 के आम बजट में लघु परमाणु संयंत्रों के लिए सरकार ने बड़े बजट का प्रावधान किया था। इस क्षेत्र में नया प्रयोग करते हुए पहली बार निजी कंपनियों को लघु परमाणु संयंत्र समूचे देश में स्थापित करने का अवसर दिया जाएगा। कालांतर में विदेशी कंपनियों को भी परमाणु संयंत्र लगाने की अनुमति दी जा सकेगी। साथ ही माइग्रूलर (प्रतिरूपक) रिपेक्टर के आधुनिकीकरण के लिए शोध और विकास पर भी धनराशि खर्च की जाएगी। जिससे परमाणु ऊर्जा में नई प्रौद्योगिकी का विकास हो, इसे पीपीवी मॉडल पर क्रियान्वित किया जाएगा। इसका उद्देश्य देश में स्वच्छ एवं वैकल्पिक बिजली को बढ़ावा देना है। इसी साल फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका यात्रा पर गए थे, तब भारत में छोटे परमाणु संयंत्र लगाने और भारत में ही उत्पादन करने का समझौता हुआ था। एआई के दौर में ऊर्जा की खपत असाधारण रूप से बढ़ने की उम्मीद है। यह एक बड़ा कंप्यूटर की भांश का कुटिम बुद्धि से जुड़ा मॉडल है। भाषा मॉडल ऐसे मशीन लर्निंग मॉडल हैं, जो मानव भाषा के पाठ को समझ सकते हैं और सृजित भी कर सकते हैं। ये मॉडल भाषा के बड़े डेटा भंडार का विश्लेषण करने पर भी सक्षम

होते हैं। सुपर और क्वांटम कंप्यूटर में इसी एआई की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए परमाणु ऊर्जा की जरूरत लघु परमाणु संयंत्रों से ही संभव है। स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन में इसे क्रांतिकारी पहल माना जा रहा है।

विकसित भारत के लिए ऊर्जा की उपलब्धता एक बड़ी जरूरत है। इसलिए सरकार सिर्फ पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भर नहीं रहना चाहती है। अधिराज सिंदूर के बाद जिस तरह से हमारी सेना में पाकिस्तान के आतंकी और गैर-सैन्य ठिकानों को ध्वस्त किया था, उन आयुधों के निर्माण और संचालन के लिए भी परमाणु ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी है। इस परिप्रेक्ष्य में सौर और पवन ऊर्जा पर सरकार पहले ही काफी कुछ कर चुकी है। अतएव अब फोकस परमाणु ऊर्जा पर केंद्रित है। क्योंकि इसमें संभावनाएं अधिक हैं। आम बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने ऊर्जा सुरक्षा को सरकार की नौ प्राथमिकताओं में गिना था। ऊर्जा बदलाव के संकेत में एक नीतिगत दस्तावेज तैयार करने की बात भी कही गई है। इससे यह तय होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में किस तरह से पारंपरिक ऊर्जा की जगह धीरे-धीरे अपारंपरिक ऊर्जा के स्रोत का महत्व बढ़ रहा है। यह दस्तावेज ऊर्जा क्षेत्र में रोजगार, विकास और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों का भी समाधान खोजेगा। अतएव इसी परिप्रेक्ष्य में निक्केल, कोबाल्ट,

तांबा और लिथियम जैसी धातुओं के उत्पादों के आयात पर शुल्क घटाया है। इन उत्पादों का प्रयोग परमाणु और सौर ऊर्जा के साथ दूसरे ऊर्जा उत्सर्जन उपायों में भी होता है। आयात सस्ता होने से इनका निर्माण भारत में करने में आसानी होगी। यही नहीं परमाणु ऊर्जा, नवीनीकरण ऊर्जा और अंतरिक्ष एवं रक्षा क्षेत्रों में इस्तेमाल होने वाली 25 धातुओं पर सीमा शुल्क को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। यानी छोटे परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के रास्ते साफ किए जा रहे हैं।

भारत में एक ओर असें से अटकी परमाणु बिजली परियोजनाओं में बिजली का उत्पादन शुरू हो रहा है, वहीं निजी निवेश से परमाणु ऊर्जा बढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने गुजरात के सूत जिले के तापी काकरापार में 22,500 करोड़ रुपये की लागत से बने 700-700 मेगावाट बिजली उत्पादन के दो परमाणु ऊर्जा संयंत्र 22 फरवरी 2024 को राष्ट्र को समर्पित कर दिए हैं। ये देश के पहले स्वदेशी परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। ये संयंत्र प्रतिवर्ष लगभग 10.4 अरब यूनिट स्वच्छ बिजली का उत्पादन करेंगे। जो गुजरात में बिजली की आवृत्ति के साथ अन्य प्रान्तों को भी बिजली देंगे। ये संयंत्र शून्य कार्बन उत्सर्जन की दिशा में आगे बढ़ने की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होंगे। भारत सरकार के उपक्रम परमाणु ऊर्जा निगम ने मध्यप्रदेश में चार नए परमाणु ऊर्जा

संयंत्र लगाने की मंजूरी दी है। जल्दी ही ये संयंत्र नीमच, देवास, सिबनी और शिवपुरी में लगेगे। सब कुछ सही रहा तो जल्दी ही इन परियोजनाओं पर काम शुरू हो जाएगा। इन संयंत्रों के शुरू हो जाने पर 1200 मेगावाट की अतिरिक्त बिजली पैदा होगी। भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता पिछले 10 साल में करीब दोगुनी हो चुकी है। 2031 तक इसके तीन गुना होने की उम्मीद है।

हालांकि परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न खतरों की आशंकाएं भी एकदम वैज्ञानिक नहीं हैं। इसलिए परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। रूस के चेर्नोबिल और जापान के फुकुशिमा परमाणु संयंत्र में हादसे के बाद इस तरह की चिंताएं लाजिमी हैं। क्योंकि वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद प्राकृतिक आपदाओं के सामने हम बौने हैं। जापान में माइज दस सेकेंड के लिए आई सुनामी नामक विरट आपदा ने फुकुशिमा की वैज्ञानिक उपलब्धियों को चकनाचूर कर दिया था। सुनिष्ट को संजीवनी देने वाले तत्व हवा, पानी और अग्नि जब न्यूनतम मर्यादाओं की सीमा लंघन कर भीषण विरटता रखते हैं तो दर्सी दिशाओं में सिर्फ और सिर्फ विनाशशाली का मंजर दिखाई देता है। इसलिए परमाणु ऊर्जा के लिए रिपेक्टर प्रदायक कंपनियों को कड़ी शर्तों के तहत मुआयजे के प्रावधान निर्धारित हों या फिर बीमा कंपनियों को दुर्घटना की स्थिति में क्षतिपूर्ति से जोड़ा जाए।

परमाणु बिजली संयंत्रों में ग्रेफाइट मॉडरेटर के रूप में प्रयोग होता है। जिसमें पानी की बहुत थोड़ी मात्रा घिल्लय करने से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के विखण्डन के समय बहुत अधिक तापमान के साथ ऊर्जा निकलती है। इस ऊर्जा का दबाव टर्बाइन को तीव्रतम गति से घुमाने का काम करता है। नतीजतन बिजली उत्पन्न होती है। रिपेक्टरों के इस उच्चतम तापमान को एक सेंटीग्रेड तक काबू में रखने के लिए रिपेक्टरों पर ठंडे पानी की निरंतर प्रवाह धाराएं छोड़ी जाती हैं। हालांकि प्राकृतिक अथवा अन्य आपदा की स्थिति में ये परमाणु संयंत्र अचूक कंप्यूटर प्रणाली से संचालित व नियंत्रित होने के कारण खुद-ब-खुद बंद हो जाते हैं। लेकिन इस अवस्था में विशेषाभयसी स्थिति यह होती है कि जल से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का नाभिकीय विखण्डन तो थम जाता है, किंतु रासायनिक प्रतिक्रियाएं और भौतिक दबाव एकाएक नहीं धमते। गोया, जलधारा का प्रवाह बंद होते ही रिपेक्टरों का तापमान 5000 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़कर 10000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। यह तापमान जीव-जंतुओं को तो क्या स्टील जैसी ठोस धातु को भी पल भर में गला देता है। इस लिहाज से इन संयंत्रों के संभावित खतरों को एकाएक नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

परमाणु ऊर्जा नागरिक उत्तरदायित्व अधिनियम

अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल के दौरान छह साल से अटके असेन्य परमाणु ऊर्जा अनुबंध पर समझौता नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल की शुरुआत में ही हो गया था। मोदी की वाक्यमृता के चलते ओबामा अमेरिका न्यूक्लियर मैट्रियल ट्रेक करने की विवाददास्य भाग से पीछे हट गए थे। इसी वजह से दोनों देशों के बीच यह समझौता रुका हुआ था। इस करार की बड़ी सफलता यह रही कि भारत को हुकना नहीं पड़ा और अमेरिका संतुष्ट हो गया था। इस मुद्दे के सिलसिले में दोनों देशों ने चतुर्दश यह बतती कि परमाणु ऊर्जा नागरिक उत्तरदायित्व अधिनियम में संशोधन की जरूरत नहीं पड़ी। इस परमाणु करार को अमल में लाने के बाबत सबसे बड़ी बाधा इस कानून का उपबंध 17 था। इसमें प्रावधान है कि यदि अमेरिकी उपकरणों के कारण भारत में कोई आसदी होती है तो परमाणु संयंत्र प्रदाता कंपनी को नुकसान की भरपाई करनी होगी। जाहिर है, यह शर्त दुर्घटना होने की स्थिति में आपूर्तिकर्ता को सीधे-सीधे जिम्मेदार ठहराती है। इसीलिए 2008 में इस समझौते के हो चुकने के बावजूद कोई विदेशी परमाणु ऊर्जा कंपनी भारत नहीं आई। जबकि डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली संलग्न सरकार ने इस करार को लागू करने के लिए सरकार ही दाय पर लगा दी थी। इस कानून में संसद में वामदलों की मांग के चलते यह कठोर शर्त जोड़ी गई थी।

इस शर्त को शिथिल किए जाने के सिलसिले में अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों का कहना था कि भारत वैश्विक नियमों का पालन करे। इन नियमों के तहत दुर्घटना की प्राथमिक जिम्मेदारी संचालित कंपनी की होती है। इस क्रम में भारत की दुविधा यह थी कि हमारे यहां सभी परमाणु संयंत्रों का संचालन सरकारी कंपनी



'भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम' करती है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन करने का मतलब था, दुर्घटना की स्थिति में सरकार को मुआयजे की अदायगी झेलने की मजबूरी? उत्तरदायित्व कानून में एक अन्य विवाददास्य शर्त दुर्घटना के समय असीमित जिम्मेदारी की भी जुड़ी थी। इस शर्त की वजह से अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा कंपनियों को बीमाकर्ता कंपनी तलाशने में मुश्किलें पेश आ रही थीं क्योंकि

कोई भी बीमा कंपनी परमाणु संयंत्रों से जुड़ी दुर्घटना का संपूर्ण बीमा भार झेलने का जोखिम नहीं उठाती। दरअसल ऐसा इसलिए है, क्योंकि परमाणु दुर्घटनाएं इतनी बड़ी और व्यापक हो सकती हैं कि कोई एक दो बीमा कंपनियां इसकी भरपाई कर ही नहीं सकतीं। रूस के चेर्नोबिल और जापान के फुकुशिमा में घटी परमाणु दुर्घटनाएं इसकी बानगियां हैं। इस नजरिए से लघु परमाणु ऊर्जा संयंत्र भविष्य में उपयोगी साबित हो सकते हैं।

चिंता का विषय जलाशयों का घटता स्तर



पर्यावरण की फिक

डॉ. प्रकाश सिंघ

पर्यावरणविद्

आज जलाशयों की कमी हमारे देश सहित पूरी दुनिया में एक बड़ी समस्या बन गई है। जलाशय पेयजल का मुख्य स्रोत हैं, लेकिन उद्योग, कृषि, बिजली उत्पादन और पारिस्थितिक संतुलन में भी महत्वपूर्ण हैं। अक्सर जलाशयों में जलस्तर पिछले कुछ वर्षों में तेजी से गिर रहा है, जो जलवायु परिवर्तन, मानसून के असंतुलन और लगातार सूखे से हुआ है। इसका प्रभाव न केवल मनुष्यों पर बल्कि जीव-जंतुओं और पर्यावरण पर भी है। भारत में जारी पानी की रिपोर्ट कार्ड के अनुसार देश के 161 जलाशयों में केवल 4.2 प्रतिशत ही पानी शेष हैं और आगे लगातार घट रहा है। गिरने वाले जल स्तर के कई कारण हो सकते हैं उनमें जल दोहन का अधिकतम सबसे बड़ा

कारण है। खेती में अधिक पानी वाली फसलों का उत्पादन, खासकर पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में, भूजल को तेजी से कम कर रहा है। इसके अलावा, औद्योगिकीकरण, बढ़ती आबादी और शहरीकरण ने जल स्रोतों पर दबाव बढ़ा दिया है। वन क्षेत्रों की कटाई और कंक्रीट के जंगलों ने जलग्रहण क्षेत्रों को नष्ट कर दिया है, जिससे बारिश का पानी जमीन में नहीं जा पाता और जलाशयों को भर नहीं पाता। हर वर्ष बढ़ता तापमान भी वजह है। बढ़ते तापमान के कारण ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं जिससे जल का भंडार ही कम नहीं हो रहा है बल्कि तेजी से पानी बहने से वर्षा भी बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। भारत में मानसून की अनियमितता से जलाशयों में जल स्तर में गिरावट आ सकती है। इस संकट से पूरा समाज प्रभावित होता है। किसानों को फसलों के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिलता, जिससे उत्पादन कम होता है और आर्थिक हालात खराब होते हैं। देश में सिर्फ 4.5 प्रतिशत कृषि भूमि ही सिंचित है जो कि मुख्यतः भूजल पर निर्भर हैं। हमारे देश की कुल 143 मिलियन हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि का लगभग 55

प्रतिशत वर्षावर्षित है तथा बरानी खेती के अंतर्गत आता है। देश में लगभग 95 प्रतिशत जंगल व बाजरा तथा 90 प्रतिशत मोटे अनाजों का उत्पादन वर्षा आर्षित क्षेत्रों से ही आता है। इसके अलावा 91 प्रतिशत दालों और 85 प्रतिशत तिलहन की पैदावार भी बरानी क्षेत्रों में होती है। शहरों में अनियमित जल वितरण से गरीब वर्ग सबसे अधिक प्रभावित होता है। वहीं, जलविद्युत परियोजनाओं में उत्पादित बिजली की मात्रा भी घट जाती है, जिससे ऊर्जा संकट उत्पन्न हो सकता है। जलाशयों का सूखना स्थानीय पारिस्थितिकी पर असर डालता है। जैसे-जैसे मछलियों की प्रजातियाँ विलुप्त होने लगती हैं, इससे पक्षियों का प्रवास प्रभावित होता है। जलाशयों का जल जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है और जल स्तर में गिरावट से पारिस्थितिकी क्षति हो सकती है।

इस खराब स्थिति से निपटने के लिए सब लोग मिलकर काम करना चाहिए। पहले, बारिश का पानी भूजल के रूप में सुरक्षित रखने के लिए वर्षा जल संयोजन अनिवार्य होना चाहिए। डिप और

डिप्रेस्सर सिंचाई जैसी आधुनिक जल संरक्षण तकनीक का प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। किसानों को समय समय पर कृषि रसायनों व रसायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग के लिए उचित परामर्श देकर भी भूजल पर इनके दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है। इसके लिए किसानों को उर्वरकों की उपयुक्त प्रयोग विधि व उनके प्रयोग करने के उचित समय की जानकारी देना अति आवश्यक है। इस प्रकार प्रयोग किए गए उर्वरकों का पूरा पूरा फायदा फसल को मिलेगा। साथ ही भूजल की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। जल बचत के लिए आम लोगों को शिक्षित और प्रेरित करना चाहिए। साथ ही, सरकार को जल प्रबंधन के कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी बनाना चाहिए। भूजल की बढ़ती की लेकर सख्त कायदे कानून बनाए जाने चाहिए। इस संबंध में जन जागरूकता बहुत जरूरी है। लोगों को बताना होगा कि भूजल की एक बूंद को मुदा सतह पर पहुंचाने में वैज्ञानिकों व किसानों को कितना परसना बहाना पड़ता है। यदि आज हम इस दिश में ठोस कदम नहीं उठाते, तो आने वाली पीढ़ियाँ जल संकट का सामना करनी पड़ेगी।

पानी पाऊच और बोटलों की नही हो रहीं जांच

-बद्रीप्रसाद कौरव

जगत प्रवाह, ग्राउंडवॉटर। गर्मी काल शुरू होते ही पानी के पाऊच की मांग बढ़ने लगती है। लोगों को ठंडा व शुद्ध पानी के नाम पर मांगा व एक्स वायरी तारीख का पानी बेचा जा रहा है, जिससे जन स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की पूरी आशंका है।

खिले के होटलों, रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म, बस स्टैंड, चाप की दुकानों पर पान ठेला पर पाऊच के पैकेट में उत्पादन तिथि का कोई उल्लेख नहीं है। उत्पादन तिथि से एक महिने के भीतर उपयोग किए जाने की बात लिखी हुई है लेकिन लोगों को उत्पादन तिथि ही नहीं बताई जा रही है, जिससे पैकेट बंद

पानी के उत्पादन तिथि को लेकर लोगों में संशय है। लोग स्वच्छ व शुद्ध पानी पीने की चाह में असुरक्षित और अशुद्ध पानी पी रहे हैं। पानी पाऊच, बोटल पैकेटिंग में प्रशासन के जिम्मेदार निरीक्षकों द्वारा कभी जांच कारवाई नहीं की जा रही है।

विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर एम्स भोपाल में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन



-समता पाठक

जगत प्रवाह, भोपाल। एम्स भोपाल ने कार्यपालक निदेशक प्रो. (डॉ.) अजय सिंह के मार्गदर्शन में 31 मई 2025 को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर विविध जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दिवस का उद्देश्य तंबाकू और उसके उत्पादों के सेवन से होने वाले स्वास्थ्य, पारिवारिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय नुकसान के प्रति लोगों को जागरूक करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) हर वर्ष 31 मई को इस दिवस का आयोजन करता है। वर्ष 2025 के लिए इसका थीम है - "अपील को उजागर करना: तंबाकू और निकोटीन उत्पादों पर उद्योग की रणनीति को उजागर करना"। यह थीम तंबाकू व निकोटीन उद्योगों द्वारा विशेषकर युवाओं को लक्ष्य कर अपने उत्पादों को आकर्षक दिखाने के लिए अपनाई जा रही भ्रमक रणनीतियों को सामने लाने और उन्हें चुनौती

देने पर केंद्रित है। तंबाकू का सेवन विश्व स्तर पर एक गंभीर स्वास्थ्य संकट बना हुआ है। यह फेफड़ों, मुंह, गले, मूत्राशय, अग्न्याशय, बृहदान्त्र, और गर्भाशय ग्रीवा जैसे कई अंगों के कैंसर का प्रमुख कारण है। अनुमानों के अनुसार, तंबाकू के उपयोग से हर वर्ष विश्व में एक करोड़ से अधिक लोगों की मृत्यु होती है। इसके अलावा, तंबाकू पर्यावरण पर भी गहरा नकारात्मक प्रभाव डालता है। इस अवसर पर प्रो. (डॉ.) अजय सिंह ने कहा: "तंबाकू निषेध दिवस न केवल स्वास्थ्य जागरूकता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह युवाओं और समाज को तंबाकू और निकोटीन उद्योगों की भ्रमक रणनीतियों से विरुद्ध जागरूक और सतर्क बनाने का भी एक सशक्त माध्यम है। एम्स भोपाल इस दिशा में निरंतर प्रयास करे, बल्कि उनकी रोकथाम और जनजागरूकता में भी अग्रणी भूमिका निभाए।"



देवी अहिल्या बाई होल्कर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन

-अमित राजपूत

जगत प्रवाह, देवरी। म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग भोपाल के

निर्देशानुसार शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय देवरी में दिनांक 31 मई 2025 को लोकमता देवी अहिल्या बाई होल्कर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. ओम प्रकाश दुबे ने लोकमता देवी अहिल्या के जीवन से जुड़े जनकल्याणकारी कार्यों को सज्ज्ञ किया। चित्रकला प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने प्रतिभागीता की जिनमें कु. कीर्ति कोरी बी.ए. प्रथम वर्ष ने प्रथम स्थान, कु. जागृति लोधी बी.ए. प्रथम वर्ष ने द्वितीय एवं कु. म्हाक बतना बी.ए. प्रथम वर्ष ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर डॉ. कलम सिंह डुड्डे, शिक्षाल अहिरवार, भगवत सिंह पटेल, धर्मेन्द्र अल्लाह एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे।

टू व्हीलर वाहन एवं देशी शराब के 200 क्वार्टर जप्त

-नरेन्द्र दीक्षित

जगत प्रवाह, जमिंदारपुरा। कलेक्टर नर्मदापुरम सोनिया मीना के अवैध शराब विक्रय निर्माण के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश एवं जिला आबकारी अधिकारी अरविंद सागर के मार्गदर्शन में जिला नर्मदापुरम में अवैध मदिरा परिवहन संग्रहण, विक्रय, निर्माण के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत औद्योगिक क्षेत्र इटारसी में आबकारी टीम द्वारा इटारसी-धरम कुंडी मार्ग पर ग्राम जुझारपुर के पास सड़ह के आधार पर एक टू व्हीलर वाहन टीवीएस जूफ़िटर ZX का पौछा किया गया। ग्राम

जुझारपुर में इंडियन ऑयल डिपो के पास उक्त वाहन क्रमांक MP05 NB9134 को रोककर तलाशी लेने पर टीवीएस जूफ़िटर वाहन में रखे देशी शराब के 200 क्वार्टर जप्त किए गये। वाहन चालक अरुणो योगेश शर्मा पिता दिनेश शर्मा उम्र लगभग 35 वर्ष निवासी जुझारपुर थाना पथरोटा जिला नर्मदापुरम को मौके से गिरफ्तार कर, उनके विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) के तहत प्रकरण कायम किया गया। उक्त कार्यवाही में जप्त टू व्हीलर वाहन एवं देशी शराब की कीमत लगभग 65,000 रुपए आंकी गई है।



विकसित बस्तर की ओर



श्री विनय कुमार
संघीय पंचायती राज मंत्रालय

श्री नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री

बस्तर क्षेत्र में कृषक, महिला, युवा उद्यमी और आदिवासी समुदायों के समावेशी विकास के लिए नई रणनीति

कृषि



- किसानों की आय बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाएं
- कृषि उत्पादों की बाजारों तक पहुंच और समर्थन को सुदृढ़
- विभिन्न समुदायों की संस्थाओं के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षण
- कृषि मशीनरीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा दिए गए सब्सिडी

पर्यटन



- पर्यटन संसाधनों को प्रमोट करने के लिए प्रचारित
- पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़
- पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़
- पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़

कौशल उन्नयन



- कौशल विकास कार्यक्रमों को प्रमोट करने के लिए
- 40 हजार कौशल विकास कार्यक्रमों को प्रमोट करने के लिए
- कौशल विकास कार्यक्रमों को प्रमोट करने के लिए
- कौशल विकास कार्यक्रमों को प्रमोट करने के लिए

उद्योग



- नई उद्योग नीति को प्रमोट करने के लिए
- उद्योगों को प्रमोट करने के लिए
- उद्योगों को प्रमोट करने के लिए
- उद्योगों को प्रमोट करने के लिए

सुशासन से समृद्धि की ओर

